



नागरकि समाज संगठनों की भूमिका की पुनर्रक्तिप्रयत्न

यह संपादकीय 14/10/2024 को हिंस्तान टाइम्स में प्रकाशित [\[१\]\[२\]\[३\]](#) “*Civil society organizations too need to be accountable*” पर आधारित है। यह लेख भारत में नागरिक समाज संगठनों के बीच जवाबदेही की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाता है, इस बात पर ज़ोर देता है कि सार्वजनिक नीतिपर उनका प्रभाव कानूनी मानकों के अनुपालन पर आधारित होना चाहिए। विदेशी योगदान वनियमन अधनियम के हालया उल्लंघन ने जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सदिधांतों के साथ संरेखण की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

परलिमिस के लिये: [नागरकि समाज संगठन](#), [वदिशी अंशदान वनियिमन अधनियिम, 2010](#), [सूचना का अधकिर \(RTI\)](#), [दवियांगजनों के अधकिर अधनियिम, 2016](#), [चुनावी बॉण्ड योजना](#), [डेमोक्रेटिक रफिओर्म्स एसोसिएशन](#), [सब-नयोजति महला एसोसिएशन](#), [आधार](#), [मज़दूर कसिन शकत्ति संगठन](#), [विश्व परेस सवतंतरता सुचाकांक](#), [कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरवायिति](#)।

मेनस के लिये: भारत में नागरकि समाज संगठनों की भूमिका, भारत में नागरकि समाज संगठनों से संबंधित प्रमुख मद्दे।

भारत में, **नागरकि समाज संगठन** सामाजिक न्याय और नीतिसुधार के समर्थन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं, फरि भी वे प्रायः अपवादवाद के आवरण में कार्य करते हैं तथा कानूनी जाँच का होने पर राज्य द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। यह द्वंद्व जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

वदिशी अंशादान वनियिम, 2010 के उल्लंघन के लिये कुछ थकि टैंक के खलिफ हाल ही में की गई कार्रवाई उनके संचालन में अनुपालन और पारदर्शता के महत्त्व को रेखांकित करती है। सार्वजनिक नीति और राय को प्रभावित करने वाली संस्थाओं के रूप में, सीएसओ को जनता का वशिवास बनाए रखने तथा नागरिक समाज की अखंडता को सुरक्षित रखने हेतु अपने वयवहार को लोकतांत्रकि सदिधार्तों एवं कानूनी शासन के अनुरूप करना चाहयि।

भारत में नागरकि समाज संगठनों की भूमिका क्या है?

- **अधिकारों की रक्षा और नीतिगत प्रभाव:** भारत में नागरकि समाज संगठन सीमांत समूहों के लिये अधिकारों की रक्षा और नीतिगत नियमों को प्रभावित करने में महत्वपूरण भूमिका नभिते हैं।
 - वे नागरकिं और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं तथा महत्वपूरण मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं।
 - अनुसंधान, अभियान और पैरवी प्रयासों के माध्यम से, नागरकि समाज संगठन कानून तथा सरकारी कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूरण भूमिका नभिते हैं।
 - उदाहरणस्वरूप, मज़दूर कसिन शक्ति संगठन द्वारा शुरू किया गया [सुचना का अधिकार \(RTI\)](#) आंदोलन है, जिसके परणिमस्वरूप वर्ष 2005 में RTI अधिनियम पारित हुआ।
 - इसका एक हालिया उदाहरण नागरकि समाज संगठनों की भूमिका है, जिन्होंने [दवियांग जनों के अधिकार अधिनियम, 2016](#) का समर्थन किया, जिसके परणिमस्वरूप इसका कार्यान्वयन और बाद में संशोधन हुए।
 - राष्ट्रीय दवियांग जन रोजगार संवरद्धन केंद्र (NCPEDP) जैसे संगठन इस समर्थन में सबसे आगे रहे हैं।
 - **सामाजिक सेवा वितरण:** सामाजिक संगठन सार्वजनिक सेवा वितरण में कमी को दूर करने में महत्वपूरण योगदान देते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सरकार की पहुँच सीमित है।
 - वे स्वास्थ्य सेवा, शक्तिशाली, स्वच्छता और आपदा राहत में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं तथा अक्सर सबसे कमज़ोर समुदायों तक पहुँचते हैं।
 - [कोवडि-19 महामारी](#) के दौरान, CSO ने समुदायों की सहायता करने में महत्वपूरण भूमिका नभिई। उदाहरण के लिये, एक प्रमुख CSO 'गूंज' ने 'राहत' अभियान शुरू किया।
 - **शासन और जवाबदेही:** नागरकि समाज संगठन शासन में पारदर्शता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए नागरिकता के रूप में कार्य करते हैं।
 - वे सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी करते हैं, सामाजिक ऑफिटि का संचालन करते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जिसके माध्यम से लोकतांत्रक प्रक्रयाएँ तेज़ होती हैं।
 - उदाहरण के लिये, [एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफिंर्समस](#) चुनावी सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूरण भूमिका नभिई रहा है, जैसा कविरष 2024 में
 - चुनावी बॉण्डों के विश्लेषण और मतदाताओं के सूचना के अधिकार हेतु अभियान ने महत्वपूरण सार्वजनिक चर्चा और कानूनी चुनौतियों

- को उत्पन्न किया है, जसिकी परणित फिरवरी 2024 में **चुनावी बॉण्ड योजना** को रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के हालयि नरिण्य के रूप में हुई।
- **सामुदायकि लामबंदी और सशक्तीकरण:** सामुदायकि संगठन समुदायों को लामबंद करने, अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हाशए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
 - वे सामूहिकि कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं और स्थानीय नेतृत्व का विकास करते हैं, जसिसे समुदाय अपनी चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनता है।
 - उदाहरण के लिये, **स्व-नियोजित महलिए एसोसिएशन (SEWA)** अनौपचारकि क्षेत्र की महलिए शरमकिं को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
 - 18 राज्यों में स्व-नियोजित महलिए एसोसिएशन के साथ 2.9 मलियन शरमकि जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन शरमकिं के अधिकारों का सफलतापूर्वक समर्थन किया है, जसिके प्रणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रविरत्न हुए हैं।
 - **नवाचार और सामाजिकि उद्यमता:** नागरकि समाज संगठन अक्सर सामाजिकि समस्याओं के लिये नवीन समाधान विकसिति करने, सामाजिकि उद्यमता को बढ़ावा देने और सतत विकास को समर्थन देने में अग्रणी भूमिका नभिते हैं।
 - वे नए तरीकों का परीक्षण करते हैं, जनिहें बाद में सरकार द्वारा बढ़ाया या अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिये, 'अक्षय पात्र फाउंडेशन' ने अपने केंद्रीकृत रसोई के माध्यम से स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में आवश्यक योगदान दिया है।
 - वर्ष 2023 तक, वे 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 22,367 स्कूलों में प्रत्येक 2 मलियन से अधिकि बच्चों को सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो दरशाता है कि कैसे नागरकि समाज संगठन (CSOs) बड़े पैमाने पर सार्वजनिकि सेवा वितरण को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
 - **प्रयावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई:** हाल के वर्षों में, भारत में प्रयावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने में नागरकि समाज संगठन (CSOs) की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण सदिध हुई है।
 - वे जागरूकता बढ़ाते हैं, अनुसंधान करते हैं और सतत विकास हेतु ज़मीनी स्तर पर पहल करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, **सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE)** ने भारत की जलवायु नीतिको आयाम देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिई है। उनके शोध और समर्थन के प्रयासों ने न केवल वाहन उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन में सहायता की है, बल्कि निवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है।
 - वर्ष 2023 में, CSE की "भारत के प्रयावरण की स्थिति" रपिरेट ने वायु प्रदूषण और जलवायु प्रविरत्न शमन रणनीतियों पर नीतिगत चर्चाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
 - **डिजिटल अधिकार और साइबर सुरक्षा:** जैसे-जैसे भारत तेज़ी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, नागरकि समाज संगठन (CSO) डिजिटल अधिकारों की रक्षा, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच सुनिश्चिति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
 - इंटरनेट फरीडम फाउंडेशन (IFF) जैसे संगठन इस आंदोलन में अग्रणी रहे हैं। निगरानी तकनीकों को चुनौती देने, डेटा गोपनीयता की रक्षा करने और नेट न्यूट्रॉलिटी को बढ़ावा देने में IFF का समर्थन तथा कानूनी हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण रहे हैं।
 - **आधार** बायोमेट्रिकि और चेहरे की पहचान आधारति उपस्थिति प्रणालयों के उपयोग के खिलाफ उनके अभियान ने सुरक्षा आवश्यकताओं तथा गोपनीयता अधिकारों के मध्य संतुलन बनाने पर राष्ट्रीय बहस को प्रेरित किया है।
 - **नागरकि सहभागता और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना:** नागरकि समाज संगठन नागरकि सहभागता और सहभागी शासन को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को मज़बूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
 - वे नरिण्य लेने की प्रक्रयाओं में नागरकि भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और सकरणि नागरकिता की संस्कृतिको बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में **मज़दूर कसिन शक्ति संगठन** योजनाओं के सहभागी सामाजिकि ऑडिट में अग्रणी रहा है।
 - PRS लेजिस्लेटिवि रसिरच जैसे संगठन जटिल विधायी प्रक्रयाओं के बारे में नागरकिं को जागरूक करने हेतु प्रयास कर रहे हैं।

भारत में नागरकि समाज संगठनों से संबंधित प्रमुख मुददे क्या हैं?

- **वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ और वित्तीय स्थिरता:** भारत में नागरकि समाज संगठनों को स्थायी और विविध वित्तपोषण स्रोत प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - वर्ष 2020 में विदेशी अंशदान (वनियिमन) अधनियम (एफसीआरए) संशोधनों ने विदेशी वित्तपोषण को और अधिकि प्रतिविधिति कर दिया है, जसिसे कई संगठनों का संचालन प्रभावित हुआ है।
 - घरेलू परोपकार इस कमी को प्रभावी रूप से पूरा नहीं कर सका है, जसिसे कई नागरकि समाज संगठन आरथकि रूप से कमज़ोर हो गए हैं।
 - एक हालयि रपिरेट के अनुसार, 54% सीएसओ ने कोवडि-19 के बाद वित्तपोषण में कमी के आँकड़ों को दरशाया।
 - इस वित्तीय अस्थिरिता ने कई संगठनों को अपने परचालन में कटौती करने या पूरी तरह से बंद करने के लिये मज़बूर कर दिया है, जसिकी विशेष रूप से सीमांत समुदायों के साथ कार्य करने वाले ज़मीनी स्तर के संगठनों पर अधिकि प्रभाव पड़ा है।
- **वनियिमकि वातावरण और सरकारी जाँच:** भारत में नागरकि समाज संगठनों के लिये वनियिमकि प्रदिव्यात्मकि होता जा रहा है। वर्ष 1976 से अब तक कुल 20,701 गैर-सरकारी संगठन अपने FCRA लाइसेंस से वंचित हो गए हैं।
 - इस गहन जाँच के कारण नागरकि समाज संगठनों, विशेषकर मानवाधिकार या प्रयावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्य करने वाले संगठनों में सेल्फ-सेसरशपि की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जसिसे सामाजिकि प्रविरत्न में उनकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है।
- **जवाबदेही और पारदरशता का अभाव:** जवकनागरकि समाज संगठन शासन में पारदरशता का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ को स्वयं जवाबदेही और पारदरशता के अभाव के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है।
 - अपरयाप्त वित्तीय रपिरेटि, अस्पष्ट नरिण्य-प्रक्रया, तथा गतविधियों और परणामों का सीमित सार्वजनिकि प्रकटीकरण, कुछ संगठनों में जनता के विश्वास को खत्म कर रहा है।
 - वर्ष 2019 में, महलिए एवं बाल विकास मंत्रालय ने सरकारी आवंटति धन का दुरुपयोग करने और खरच न की गई राशविप्रस न करने के आरोप में NGO इंडियन काउंसल फॉर चाइल्ड वेलफेयर (ICCW) के विरुद्ध FIR दर्ज की है।
 - पारदरशता की कमी से जनता का विश्वास कम होता है।

- **राजनीतिक धुरुवीकरण:** भारत में बढ़ते राजनीतिक धुरुवीकरण ने नागरकि समाज संगठनों, वशिष्ठ रूप से मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार या प्रयावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्य करने वाले नागरकि समाज संगठनों के लिये, चुनौतीपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया है।
 - कुछ संगठनों पर "राष्ट्र-वरिधी" होने या भारत के हतों के वरिद्ध कार्य करने के आरोप लगते हैं, जिसके कारण जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न होता है तथा कभी-कभी कानूनी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।
 - वर्ष 2023 के वशिष्ठ प्रेस सवत्तरता सूचकांक में भारत को 180 देशों में 161वाँ स्थान दिया गया है, जो मुक्त अभियक्ति पर व्यापक प्रतिविधों को दर्शाता है, जो नागरकि समाज संगठनों को भी प्रभावित करते हैं।
 - इस धुरुवीकृत वातावरण ने कुछ संगठनों को सेलफ-रेसर करने या कुछ मुद्दों से बचने के लिये प्रेरित किया है, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में उनकी प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।
- **सीमित सहयोग और क्षेत्रीय विखिंडन:** भारत में CSO क्षेत्र अक्सर संगठनों के बीच सीमित सहयोग और समन्वय से ग्रस्त रहता है, जिसके परणिमस्वरूप प्रयासों का दोहराव और संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है।
 - वित्तपोषण और मानवता के लिये प्रतिसिपरदधा कभी-कभी उन साझेदारियों में बाधा उत्पन्न करती है जो सामूहिक प्रभाव को बढ़ा सकती है।
 - यह विखिंडन न केवल नागरकि समाज के सामूहिक प्रभाव को कम करता है, बल्कि नीतिओं और सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों को भी कमज़ोर करता है।
- **प्रभाव मापन और रपोर्टिंग चुनौतियाँ:** CSO अक्सर अपने प्रभाव को प्रभावी ढंग से मापने और संप्रेषण करने में संघर्ष करते हैं, जो कि वित्तपोषण को आक्रमणित करने तथा हतिधारकों के लिये मूल्यांकन प्रणालियों या आकलन करने की क्षमता का अभाव है।
 - कई संगठनों में मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों या आकलन करने की क्षमता का अभाव है।
 - प्रभावी मापन में यह अंतर न केवल संगठनों की अपने कार्यकर्मों को बेहतर बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि दिताओं और नीतिनिर्माताओं के समक्ष अपने कार्य को उचित ठहराना भी कठिन बना देता है, जिसके परणिमस्वरूप समर्थन और वित्तपोषण में कमी आ सकती है।
- **डिजिटल वभिजन और तकनीकी चुनौतियाँ:** समाज के तेज़ी से डिजिटलीकरण ने CSO क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण डिजिटल वभिजन को उजागर कर दिया है।
 - जबकि कुछ संगठनों ने अपने कार्य के लिये प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है, कई, वशिष्ठ रूप से छोटे और ग्रामीण CSO, सीमित डिजिटल बुनियादी ढाँचे और कौशल के साथ संघर्ष कर रहे हैं।
 - एक हालिया सर्वेक्षण में कहा गया है कि 95% नागरकि समाज संगठनों का कहना है कि इंटरनेट उनके कार्य क्षमता हेतु महत्वपूर्ण है, जबकि 78% के पास ऐसा करने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी उपकरणों का अभाव है।
 - यह डिजिटल वभिजन न केवल नागरकि समाज संगठनों की परचालन दक्षता को प्रभावित करता है, बल्कि तेज़ी से डिजिटल वशिष्ठ में उनकी पहुँच और प्रभाव को भी सीमित करता है।
- **स्वयंसेवक प्रबंधन और प्रतिधारण:** कई नागरकि समाज संगठनों को स्वयंसेवकों को आक्रमणित करने, प्रबंधित करने और बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर उनके संचालन के लिये महत्वपूर्ण होते हैं।
 - स्वयंसेवकों की उच्च ट्रन-ओवर रेट और सीमित दीर्घकालिक प्रतिविद्धता कार्यकरम की निरितरता तथा संगठनात्मक विकास को बाधित कर सकती है।
 - एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 78% ने स्वयंसेवी कार्यकर्मों में कर्मचारियों की भागीदारी की सूचना दी, जबकि केवल 26% ने स्वयंसेवकों की संख्या तथा 39% ने स्वयंसेवी घंटों की संख्या की सूचना दी।
 - स्वयंसेवी सहभागिता में यह असंगतता, दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें करियान्वित करने तथा टकिऊ सामुदायिक संबंध बनाने में नागरकि समाज संगठनों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

भारत में CSO की भूमिका बढ़ाने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **वनियामक प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थिति और सरल बनाना:** सरकार आवश्यक नियंत्रण बनाए रखते हुए CSO के लिये नौकरशाही बाधाओं को कम करने हेतु FCAR और अन्य वनियामक प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थिति कर सकती है।
 - इसमें पंजीकरण और अनुपालन के लिये एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली बनाना, कागजी कार्रवाई को कम करने के लिये प्रक्रयाओं का डिजिटलीकरण करना तथा अनुमोदन के लिये स्पष्ट समय-सीमा निरिधारण करना शामिल हो सकता है।
 - वनियमन के लिये जोखमि-आधारित दृष्टिकोण को लागू करना, जहाँ अनुपालन के ट्रैक रिकॉर्ड वाले संगठनों को कम प्रतिविधों का सामना करना पड़ता है, भी लाभकारी हो सकता है। उदाहरण के लिये, गृह मंत्रालय द्वारा FCRA वार्षिक रिट्रैन को ऑनलाइन जमा करने की अनुमतिदिने की पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसे सभी वनियामक संवाद को कवर करने के लिये वसितारति किया जा सकता है।
- **घरेलू प्रोपकार और CSO साझेदारी को बढ़ावा देना:** कर प्रोत्साहन और सरलीकृत दान प्रक्रयाओं के माध्यम से घरेलू प्रोपकार को प्रोत्साहित करने से विदेशी वित्तपोषण में गरिवट को कम करने में मदद मिल सकती है।
 - सरकार पंजीकृत नागरकि समाज संगठनों को दिये जाने वाले वित्तपोषण हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत कर कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
 - इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायतित्व (CSR) पहल के तहत CSO और कॉर्पोरेट्स के बीच मजबूत साझेदारी को सुवधाजनक बनाने से स्थायी वित्तपोषण स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं।
 - अन्य देशों के सफल मॉडलों के समान, एक राष्ट्रीय CSR-CSO मिलान मंच बनाने से सहयोग और संसाधन आवंटन दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
- **क्षमता नियमाण और कौशल विकास में नविश:** सार्वजनिक-नजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से संभावित रूप से वित्तपोषण, नागरकि समाज संगठनों के लिये राष्ट्रीय क्षमता नियमाण कार्यकरम की स्थापना से डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन तथा प्रभाव माप जैसे क्षेत्रों में कौशल अंतराल को दूर किया जा सकता है।
 - यह कार्यकरम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल, मार्गदर्शन के अवसर और विभिन्न संगठनात्मक

आकारों तथा केंद्रति क्षेत्रों के अनुरूप संसाधन प्रदान कर सकता है।

- शैक्षकि संस्थानों और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ सहयोग करने से विशेषज्ञता और संसाधन प्राप्त हो सकते हैं।
 - हाल ही में [राष्ट्रीय शक्षिका नीति 2020](#) में कौशल विकास पर ज़ोर दिया गया है, जिसका लाभ उठाकर CSO प्रबंधन को फोकस क्षेत्र के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- पारदर्शनी और जवाबदेही तंत्र को बढ़ाना: एक व्यापक, उपयोगकर्ता-अनुकूल राष्ट्रीय CSO डेटाबेस विकासित करना जिसमें वित्तीय रपोर्ट, कार्यक्रम परिणाम और प्रभाव आकलन शामिल हों, पारदर्शनी में सुधार कर सकता है तथा सार्वजनिक विश्वास का निर्माण कर सकता है।
 - इस प्लेटफॉर्म को गाइडस्टार जैसे सफल अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों के आधार पर तैयार किया जा सकता है, जिसे भारतीय संदर्भ के लिये अनुकूलति किया जा सकता है।
 - नागरिक समाज संगठनों को मानकीकृत रपोर्टिंग प्रारूप अपनाने तथा स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष ऑडिट कराने के लिये प्रोत्साहित करने से विश्वसनीयता में और वृद्धि हो सकती है।
 - सरकार उच्च पारदर्शनी मानकों को बनाए रखने वाले संगठनों को शीघ्र अनुदान अनुमोदन या कर प्रोत्साहन जैसे लाभ प्रदान करके इन प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकती है।
- सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना: क्षेत्रीय और क्षेत्रीय CSO नेटवर्क या गठबंधन बनाने से सहयोग में वृद्धि हो सकती है, प्रयासों का दोहराव कम हो सकता है, तथा सामूहिक प्रभाव बढ़ सकता है।
 - इन नेटवर्कों को नियमित सम्मेलनों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों और संयुक्त प्रयोजनों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।
 - मुद्रा-आधारित संघों के गठन को प्रोत्साहित करना, जहाँ समाज विषयों पर कार्य करने वाले नागरिक समाज संगठन संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करते हैं, इससे अधिक प्रभावी हस्तक्षेप हो सकता है।
- साक्षय-आधारित नीति निर्माण को लागू करना: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में CSO की भागीदारी के लिये औपचारिक तंत्र स्थापित करने से सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
 - इसमें प्रारंभिक सरकारी समतियों में CSO का प्रतिनिधित्व अन्विर्य करना, नियमित प्रामार्श मंचों का निर्माण करना, तथा नीतिगत नियन्यों में CSO द्वारा उत्पन्न आँकड़ों और अनुसंधान को शामिल करना शामिल हो सकता है।
 - नीति आयोग की नीतिगत चर्चाओं में नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने की हाल की पहलों का विस्तार किया जा सकता है तथा उन्हें सभी सरकारी विभागों में संस्थागत रूप दिया जा सकता है, ताकि नीति निर्माण में विधि तथा जमीनी स्तर के दृष्टिकोणों को शामिल करना सुनिश्चित हो सके।
- डिजिटल प्रविरत्न और नवाचार को बढ़ावा देना: प्रौद्योगिकी अपनाने में संगठनों को सहायता देने के लिये 'डिजिटल CSO' पहल शुरू करने से उनकी दक्षता और पहुँच बढ़ सकती है।
 - इसमें डिजिटल उपकरणों तक रायियती पहुँच प्रदान करना, डिजिटल प्रविरत्न हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और क्षेत्र के भीतर नवीन तकनीकी समाधानों को साझा करने के लिये मंच स्थापित करना शामिल हो सकता है।
 - नवाचार निधिके माध्यम से प्रौद्योगिकी कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने से भारत-विशिष्ट समाधानों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
 - सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का विस्तार सामाजिक क्षेत्र की डिजिटल आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिये किया जा सकता है।
- सामाजिक उद्यम मॉडल के माध्यम से वित्तीय स्थरिता को बढ़ाना: सामाजिक उद्यम दृष्टिकोण को शामिल करके स्थायी राजस्व मॉडल विकसित करने के लिये CSO को प्रोत्साहित करने से दाताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
 - इसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामाजिक उद्यमों के लिये कम ब्याज दर वाले ऋणों तक पहुँच तथा CSO उत्पादों एवं सेवाओं के लिये बाजार का निर्माण करके समर्थति किया जा सकता है।
 - सतत मॉडल विकसित करने में गूंज जैसे संगठनों की सफलता इस दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
- प्रभाव मापन और रपोर्टिंग को मज़बूत बनाना: CSO कार्य के विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप मानकीकृत प्रभाव मापन ढाँचे का विकास करने से प्रभाव को प्रदर्शित करने और संपर्खित करने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है।
 - इसे राष्ट्रीय प्रभाव माप संसाधन केंद्र बनाकर समर्थित किया जा सकता है, जिसमें इन ढाँचों को लागू करने के लिये नागरिक समाज संगठनों को प्रशिक्षण तथा उपकरण प्रदान किया जा सकते हैं।
 - वास्तविक समय डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने से प्रभाव रपोर्टिंग की स्टीक्टा और समयबद्धता में सुधार हो सकता है।
 - सरकार कुछ निश्चिति निधियों या लाभों तक पहुँच के लिये मानकीकृत प्रभाव रपोर्टिंग को अन्विर्य बनाने पर विचार कर सकती है, जिससे पूरे क्षेत्र में इसे अपनाने को प्रोत्साहन मिलिए।
- जन सहभागिता और स्वयंसेवा को बढ़ावा देना: स्वयंसेवा और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अभियान शुरू करने से CSO गतविधियों में जन समर्थन और भागीदारी बढ़ सकती है।
 - इसमें सामुदायिक सेवा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक डाटाबेस तैयार करना, तथा स्वयंसेवी कार्य के लिये शैक्षणिक क्रेडिट या कौशल प्रमाण-पत्र जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल हो सकता है।
 - संभावित स्वयंसेवकों को नागरिक समाज संगठनों से जोड़ने के लिये सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से सहभागिता को सुचारू बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और नीति सुधार को प्रभावित करने के लिये नागरिक समाज संगठन अपरहिर्य हैं। अपनी क्षमता, प्रदर्शनी और सहयोग को बढ़ाने के उपायों को लागू करके, नागरिक समाज संगठन एक अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज को आकार देने में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकते हैं। आगे बढ़ने हेतु सरकार और नागरिक समाज को एक साथ मिलाकर ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा जो इन संगठनों को समर्थन दे और उन्हें अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाए।

प्रश्नों का उत्तर:

भारत में सामाजिक न्याय और नीति सुधार को बढ़ावा देने में नागरकि समाज संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजयि। इन संगठनों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये उनके भीतर जवाबदेही को कैसे मजबूत किया जा सकता है?

https://youtu.be/Dcqloba_Vqo

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न:

- प्रयावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को कैसे मजबूत किया जा सकता है? प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजयि। (2015)
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधनियम (FCRA), 1976 के तहत गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले नियमों में हाल के बदलावों की आलोचनात्मक जाँच कीजयि। (2015)
- क्या सविलि सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठन आम नागरकि को लाभ पहुँचाने के लिये सार्वजनिक सेवा वितरण का कोई वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक मॉडल की चुनौतियों पर चर्चा कीजयि। (2021)
- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विकास के लिये दाता एजेंसियों पर बढ़ती नियमित विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को कम करती है? अपने उत्तर का औचित्य बताइये। (2022)
- विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और नजीकी संस्थाएँ के बीच कसितर का सहयोग सबसे अधिक उत्पादक होगा? (2024)
- सार्वजनिक धर्मारथ ट्रस्टों में भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। टपिपणी कीजयि। (2024)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nbwl-approves-road-expansion-in-ladakh-1>